

रोडवेज केवल ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के पदों को छूट दी गई है हरियाणा में किए गए कार्य के प्रकार को ध्यान में रखने के बाद रोडवेज. इसलिए, हम यह देखते हैं कि इसमें कोई कानूनी दुर्बलता नहीं है अधिसूचना 4 जून, 2005 (अनुलग्नक पी - 2) और यह उत्तर देती है आवश्यक सुप्रीम के उनके आधिपत्य द्वारा निर्धारित मानदंड संजय कुमार जैन के मामले में कोर्ट (*Supra*). इसके अलावा की सेवा याचिकाकर्ता को समाप्त कर दिया गया है. उन्होंने 19 साल से अधिक समय तक रेंडर किया था सेवा और नियम के अनुसार पेंशन दी गई है. इस प्रकार, वहाँ याचिका में कोई योग्यता नहीं है और वही खारिज होने के लिए उत्तरदायी है,

७) उपरोक्त चर्चाओं की अगली कड़ी के रूप में यह याचिका विफल हो जाती है और वही खारिज किया जाता है.

---

R.N.R.

माननीय न्यायमूर्ति के कन्नन, जे

श्याम सुंदर प्रो, MiS टीसी फिलिंग स्टेशन  
(AD HOC) HPC PETROL PUMP, विलेज AJRAWAR  
DISTRICT KURUKSHETRA, — याचिकाकर्ता

बनाम

भारत का संघ *अन्य, उत्तरदाताओं*

2009 का CPW नंबर 16469

3 मार्च, 2009 - पीएफ I

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226- पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा आउटलेट की अस्थायी डीलरशिप को रद्द करना- स्थायी आधार पर डीलरशिप का दावा करने वाला याचिकाकर्ता- विज्ञापन में पाठ कहीं भी यह नहीं दर्शाता है कि निमंत्रण पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप स्थापित करने के इच्छुक लोगों की ओर से था- निमंत्रण पेट्रोलियम कंपनी के प्रतिष्ठान खुदरा आउटलेट के लिए बिक्री या पट्टे की पेशकश के लिए था- याचिकाकर्ता को दी गई डीलरशिप लंबी अवधि के लिए नहीं थी- व्यवस्था की समाप्ति के लिए 15 दिनों का नोटिस प्रदान करने वाला

**पत्र की पेशकश दस्तावेज-विशुद्ध रूप से संविदात्मक मामला- किसी भी विशेषाधिकार रिट के माध्यम से उच्च न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं- याचिका लागत के साथ खारिज कर दी गई।**

श्याम सुंदर प्रो. MIS TC FILLING STATION (AD HOC) एचपीसी 467  
पेट्रोलपंप, विलेज AJRAWAR DISTRICT KURUKSHETRA  
वी. भारत और अन्य लोगों का संघ (क. कन्नू

आयोजित किया गया, कि विज्ञापन में पाठ कहीं भी नहीं दिखाते हैं कि निमंत्रण उन लोगों से था जो पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप स्थापित करने में रुचि रखते थे। दूसरी ओर, निमंत्रण दूसरी प्रत्यर्थी कंपनी के प्रतिष्ठान खुदरा दुकानों के लिए बिक्री या पट्टे की पेशकश के लिए था। दूसरा, संपत्ति का मालिक स्वयं विक्रेता नहीं था। मालिक याचिकाकर्ता का भाई था और विक्रेता को 30 साल की लंबी अवधि के लिए नहीं दिया गया था।

(पैरा 5)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे मामले में जहां लेन देन स्पष्ट रूप से पक्षों के बीच संबंधित अधिकारों और कर्तव्यों को बताता है, प्रोमिसरी एस्टोपल की याचिका का कोई अर्थ नहीं है। याचिकाकर्ता उस पर कब्जा रखने के बड़े अधिकार का दावा नहीं कर सकता है जो अनुबंध के तहत निश्चित किए गए विशिष्ट वादे के माध्यम से सुरक्षित है। एक सार्वजनिक निकाय के रूप में दूसरे प्रत्यर्थी का आचरण उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के लिए स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन जब दूसरे प्रत्यर्थी के कार्य संविदात्मक वादों द्वारा संचालित होते हैं और निश्चित रूप से प्रकृति में होते हैं, तो अनुबंध को रद्द करने के बारे में कुछ भी मनमाना नहीं है। हस्तक्षेप के लिए कुछ भी उपयोगी नहीं है।

(पैरा 7)

डॉ. बलराम गुप्ता, सीनियर, अधिवक्ता, आर.डी. गुप्ता, एडवोकेट, के लिए के याचिकाकर्ता

प्रतिवादी के लिए कर्मिंदर सिंह, एडवोकेट. 1-U.O.I अतुल नेहरा, प्रतिवादी, उत्तर 2 और 3 के लिए.

प्रतिवादी संख्या के लिए कोई नहीं. 4

के कानन, जे.

1. याचिकाकर्ता इस रिट याचिका के माध्यम से प्रतिवादी नं. 2-पेट्रोलियम कंपनी और कंपनी द्वारा परिसर को सौंपने या खाली और बिक्री स्थापित करने की मांग। डीलरशिप समझौते को इस आधार पर रद्द किया गया था कि आउटलेट को 15 दिनों के नोटिस के बाद अस्थायी आधार पर पेश किया गया था और इसे समाप्त करने और परिसर की डिलीवरी की आवश्यकता के लिए नोटिस दिया गया था।

(2) 2. याचिकाकर्ता इस बात से व्यथित है कि प्रतिवादी नं. 2 21 मई, 2002 को आमंत्रित किए गए व्यक्ति, जो संपत्ति के अनन्य मालिक या सह-मालिक थे, उन्हें दूसरे प्रत्यर्थी को नवीकरण विकल्प के साथ न्यूनतम 30 वर्षों की अवधि के लिए बिक्री/पट्टे के माध्यम से भूमि के भूखंड के हस्तांतरण के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करना था और इसलिए उसने इस विश्वास के साथ छुट्टी पर अपनी संपत्ति की पेशकश की थी कि उसे आउटलेट स्थापित करने के लिए लंबी अवधि की डीलरशिप भी दी जाएगी। इस तरह के विश्वास के तहत 24 जुलाई, 2003 को 30 साल की अवधि के लिए पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था और 25 अगस्त, 2005 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को डीलरशिप की पेशकश की गई थी। डीलरशिप की अवधि के निर्वाह के दौरान, दूसरे प्रतिवादी को संसद प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार की एक नीति द्वारा निर्देशित किया जाना था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) और कंपनियों के स्वामित्व वाली कंपनी संचालित (सीओसीओ) संस्थाओं को वाणिज्यिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए खुदरा दुकानों के संचालन की योजना की परिकल्पना की गई थी। इस नीति में एक वर्ष की अवधि के भीतर अस्थायी सी. ओ. सी. ओ. खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने और लंबित आशय-धारकों को ऐसी दुकानों की पेशकश करने और उन्हें सौंपने की भी परिकल्पना की गई है। नीति विवरण 6 सितंबर, 2006 को जारी किया गया था और याचिकाकर्ता की डीलरशिप योजना को रद्द करने की शुरुआत नीति में बदलाव के कारण की गई थी।

3. इस रिट याचिका द्वारा याचिकाकर्ता का प्रयास यह दिखाने के लिए था कि दूसरा प्रतिवादी, जो पूरी तरह से सरकारी कंपनी का स्वामित्व रखता था, राज्य का एक साधन था और इसकी सभी गतिविधियों का परीक्षण अनुच्छेद 14 के संवैधानिक अधिदेश के जवाब में निष्पक्षता के मापदंडों द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2006 के नीतिगत विचार में मौजूदा अनुबंधों को नहीं बदलना चाहिए जो पहले भी तैयार किए गए थे और डीलरशिप के अनुबंध को समय से पहले रद्द करना और संपत्ति को फिर से शुरू करने की मांग मनमाना और अनुचित थी। याचिकाकर्ता द्वारा डीलरशिप को स्थायी आधार पर दिए जाने का दावा किया जा रहा है, हालांकि व्यवस्था स्वयं दो साल की प्रारंभिक अवधि के लिए थी, तीसरे प्रतिवादी द्वारा आश्वासन द्वारा, जो दूसरी प्रतिवादी कंपनी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक हैं। कथित वादे पर कार्रवाई करते हुए, याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने कई लाख रुपये का पर्याप्त निवेश किया है और याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने ग्रामीण उपभोक्ताओं को लाखों रुपये के मूल्य के ऋण के आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया है। डीलरशिप की इस तरह की व्यवस्था की समय से पहले समाप्ति घोर अन्यायपूर्ण थी और

प्रत्यर्थियों को प्रोमिसरी एस्टोपेल द्वारा डीलरशिप को समाप्त करने और प्रत्यर्थी को सौंपी जाने वाली संपत्ति को वापस लेने से रोक दिया गया था। लीज के नवीकरण का विकल्प इस आधार पर प्रदान किया गया था कि उस समय जब संपत्ति की बिक्री या लीज के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, तो इस बात का कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं था कि यह बिक्री या लीज द्वारा लिया जाना था, जिसमें पेट्रोलियम आउटलेट्स की डीलरशिप देने का कोई सहवर्ती आश्वासन नहीं था और यह कि यह इरादा था कि दूसरा प्रतिवादी किसी तीसरे पक्ष को भी डीलरशिप देने की पूरी स्वतंत्रता बनाए रख सकता है।

(४) 4. यह पता लगाने के लिए कि क्या विज्ञापन में उस व्यक्ति द्वारा किसी निष्कर्ष का सुझाव दिया गया था जिसे इस तरह की प्रक्रिया के माध्यम से बिक्री या पट्टे के लिए प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित किया गया था कि उसे संपत्ति के संबंध में डीलरशिप के अनुदान का भी आश्वासन दिया जाएगा, केवल विज्ञापन के पाठ को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विज्ञापन इस प्रकार है:—

"भूमि में रुचि रखने वाले पक्षों के पूर्ण और अनन्य मालिकों या सह-मालिकों से, यदि वे पहले से ही बिक्री/पट्टे के माध्यम से भूमि के भूखंड के हस्तांतरण के लिए बिक्री/पट्टे की तारीख से पहले बिक्री के लिए पंजीकृत समझौता कर चुके हैं (नवीकरण विकल्पों के साथ न्यूनतम 30 वर्ष) मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निम्नलिखित स्थानों पर एक रीटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए"

एमएस विज्ञापन से कहीं भी यह नहीं पता चलता है कि उस व्यक्ति को भी डीलरशिप देने का कोई वादा किया गया था जो बिक्री या पट्टे पर संपत्ति की पेशकश कर रहा था। विद्वान श्री. वकील डॉ. बलराम गुप्ता ने केवल यह प्रस्तुत किया कि जिस तरह से एक समकालीन दस्तावेज आया, वह स्वयं दिखाएगा कि विज्ञापन का अर्थ डीलरशिप के अनुदान के लिए भी एक आश्वासन था। यह इंगित करते हुए कि विज्ञापन के बाद, 24 अगस्त, 2003 को याचिकाकर्ता के भाई के पक्ष में पट्टा निष्पादित किया गया था और 25 अगस्त, 2005 को लगभग दो साल के समय में याचिकाकर्ता को डीलरशिप की पेशकश की गई थी। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि 2500 वर्ग मीटर मापने वाली

संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कभी भी 30 साल की इतनी लंबी अवधि के लिए रु। शुरू में पांच साल की अवधि के लिए 4900 रुपये प्रति माह और रुपये तक के किराए में बहुत मामूली वृद्धि का प्रावधान। अंतिम पंचवर्षीय अवधि के लिए 9856 प्रति माह। मैं विद्वान वकील तर्क देता हूँ कि उसकी ओर से या किसी भी व्यक्ति की ओर से निश्चित आश्वासन के बिना इतनी बड़ी सीमा तक आत्मसमर्पण करना पूरी तरह से मूर्खता होगी कि डीलरशिप केवल मालिक या सह-मालिकों को दी जा सकती है। यह तथ्य कि डीलरशिप भी थोड़े समय के भीतर दी गई थी, इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भूमि का विज्ञापित पट्टा और आउटलेट की डीलरशिप सभी एक ही लेन-देन का हिस्सा थे, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था।

(5) मेरे विचार में विवाद, संबंधित दस्तावेजों के पाठ से अलग पूरा होता है। विज्ञापन में पाठ पहले ही निकाले जा चुके हैं और वे कहीं भी नहीं दिखाते हैं कि निमंत्रण उन लोगों से था जो पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप स्थापित करने में रुचि रखते थे। दूसरी ओर, निमंत्रण दूसरी प्रत्यर्थी कंपनी के प्रतिष्ठान खुदरा दुकानों के लिए बिक्री या पट्टे की पेशकश के लिए था। दूसरा, संपत्ति का मालिक स्वयं विक्रेता नहीं था। मालिक याचिकाकर्ता का भाई था और डीलरशिप की पेशकश याचिकाकर्ता को 30 साल की लंबी अवधि के लिए नहीं की गई थी। दूसरी ओर, डीलरशिप की पेशकश करने वाले दस्तावेज़ में खंड 2 और 3 से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह केवल अस्थायी था और दस्तावेज़ में अभिव्यक्तियों को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:

*"2. तदनुसार हम आपको एक अस्थायी डीलर के रूप में नियुक्त करते हैं केवल अस्थायी आधार विषय पर उक्त आउटलेट को संचालित करने के लिए अन्य 15 दिनों के लिए किसी भी पार्टी द्वारा समाप्ति के लिए उस ओर से नोटिस*

3. रिटेल आउटलेट व्यवसाय आपके द्वारा विशुद्ध रूप से संचालित किया जाएगा नियमित रूप से किसी भी दावे या पात्रता के बिना अस्थायी आधार डीलरशिप."

दस्तावेज़ की प्रारंभिक अवधि स्वयं एक वर्ष तक सीमित थी खंड संख्या 6 के माध्यम से और दस्तावेज़ का कार्यकाल केवल संदर्भित करता है छुट्टी और लाइसेंस के रूप में लेनदेन और आउटलेट चलाने की अनुमति अस्थायी व्यवस्था पर. इस तरह की भर्तियों के सामने यह अनुभवहीन होगा और याचिकाकर्ता के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वहाँ एक आश्वासन था स्थायी डीलरशिप.

6. जब डीलरशिप को समाप्त करने का नोटिस जारी किया गया था तो उस पर तभी हमला किया जा सकता था जब अनुबंध का कोई उल्लंघन हुआ हो। 29 जनवरी, 2009 के पत्र में उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 15 दिनों का नोटिस दिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को तदर्थ विक्रेता के रूप में प्रस्तुत करके 25 अगस्त, 2005 के ज्ञापन पत्र का संदर्भ दिया गया था। इसके बाद 2 जून, 2009 के पत्र में खुदरा दुकान को सौंपने का निर्देश दिया गया है और 19 जून, 2009 के तीसरे पत्र में याचिकाकर्ता को 25 जून, 2009 की नोटिस अवधि के बाद पेट्रोल पंप सौंपने की सलाह दी गई है याचिकाकर्ता को किसी भी विशेषाधिकार रिट के माध्यम से उपचार प्रदान करके विशुद्ध रूप से संविदात्मक मामलों में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

(7) प्रॉमिसरी एस्ट्रोपेल की दलील का किसी मामले में कोई मतलब नहीं है जहां लेन-देन स्पष्ट रूप से संबंधित अधिकार और कर्तव्यों को पूरा करता है पार्टियों के बीच. याचिकाकर्ता एक बड़े अधिकार का दावा नहीं कर सकता अनुबंध के तहत प्रमाणित विशिष्ट वादे के माध्यम से जो हासिल किया गया है, उससे अधिक कब्जे में. एक सार्वजनिक निकाय के रूप में दूसरे प्रतिवादी का आचरण उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हो सकता है लेकिन जब दूसरे प्रतिवादी की कार्रवाई संविदात्मक वादों से प्रेरित होती है और प्रकृति में निश्चित हैं, रद्दीकरण के बारे में कुछ भी मनमाना नहीं है अनुबंध का. हस्तक्षेप के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है.

(8) याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील का कहना है कि 2006 के नीतिगत विचार को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। जहां पक्षों के अधिकार अनुबंध द्वारा शासित होते हैं और अनुबंध को समाप्त करने के लिए एक तरीका निर्धारित किया गया है और वह तरीका शुरू किया गया था, याचिकाकर्ता को डीलरशिप में स्थायी स्थिति के लिए अनुरोध करने वाली रिट याचिका के माध्यम से कोई राहत नहीं मिल सकती है, नीति का बयान केवल हमारे विचार के लिए आकस्मिक है और यह जांचने के लिए अपने उचित परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किया जाना चाहिए, यदि आवश्यक हो, तो दूसरे प्रतिवादी का आचरण उचित था या नहीं। एक अस्थायी विक्रेता के हाथों से परिसर खाली करने के लिए एक नीतिगत विचार का विवरण दूसरे प्रतिवादी की मांग की तर्कसंगतता का परीक्षण करने के लिए एक अतिरिक्त आधार है, हालांकि उचित कार्य की जांच के लिए एक आवश्यक परीक्षण नहीं है।

(9) रिट याचिका पूरी तरह से योग्यता के बिना है और रुपये की अनुमानित लागत के साथ खारिज कर दी गई है। 10, 000। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि अगर उसे संपत्ति से खुद को हटाने का निर्देश

दिया जाता है तो उसे कठिनाई होगी। याचिकाकर्ता के पास उन सभी जुड़ावों के साथ संपत्ति से खुद को हटाने के लिए एक महीने की अवधि होगी जिन्हें वह संविदात्मक शर्तों के तहत हटाने का हकदार है।

**अस्वीकरण :** स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आदित्य सैनी  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी  
रेवाडी (हरियाणा)